web : www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

SJU Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, मंगलवार 19 मार्च 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-169

महत्वपूर्ण एवं खास

न्यूजीलैंड में 10 दिन के अंदर बदल जायेगा बंदूक कानून

वेलिंगटन (आरएनएस)। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में शुक्रवार को हुयी अंधाधुंध गोलीबारी और इसमें 50 से अधिक लोगों की मौत तथा इतने लोगों के घायल होने के बाद सरकार ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए बंदूक कानून को बदलने का निर्णय लिया और कहा कि 10 दिन के इस कानून को बदल दिया जायेगा।

इंडोनेशिया में 4.4 तीव्रता का भूकंप, 2 पर्यटक मरे

जकार्ता (आरएनएस)। इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप में रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद दो पर्यटकों की मौत हो गई और 44 अन्य घायल हो गए। एफे की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता सुतोपो नुग्रोहो ने कहा कि जान गंवाने वाले मलेशियाई पर्यटक भूकंप के बाद माउंट रिन्जनी के पास तियु केलेप झरने के पास आए भूस्खलन में अन्य 36 लोगों के साथ फंसे थे।

राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में एक जवान शहीद, तीन घायल

श्रीनगर (आरएनएस)। पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह करीब साढ़े पांच बजे जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सीजफायर का उल्लंघन किया है. पाकिस्तानी सेना की ओर से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है और मोर्टार भी दागे जा रहे हैं. पाकिस्तानी सेना की तरफ से हो रही इस फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया है जबकि तीन जवान जख्मी हो गए हैं. भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्रिकर के निधन पर शोक प्रकट किया

आम लोगों का मुख्यमंत्री बताया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर सोमवार को शोक प्रकट किया और कहा कि उन्हें उनकी सादगी के लिए और असाधारण प्रशासक के रूप में याद किया जायेगा। पर्रिकर के सम्मान में दो मिनट का मौन रखने के बाद कैबिनेट ने एक संकल्प पारित किया और कहा कि उनके निधन से देश ने एक सक्षम प्रशासक खो दिया जिन्हें स्नेहपूर्वक 'आम लोगों का मुख्यमंत्री' कहा जाता था।

तिहाड़ जेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड बिचौलिए मिशेल को भेजा नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को नोटिस जारी किया है. हाल ही में तिहाड़ जेल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जेल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि मिशेल फोन कॉल का गलत उपयोग कर रहे हैं. निचली अदालत ने मिशेल को 15 मिनट फोन कॉल करने की इजाजत दी थी. ऐसे में इस फैसले को चुनौती देते हुए जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट में कहा कि यह जेल मेनुअल के खिलाफ है.

दिल्ली के मुंडका में केमिकल फैक्ट्री में आग

दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. मुंडका इलाके के स्वर्ण पार्क में बनी इस फैक्ट्री में लगी आग के बाद दमकल विभाग को कॉल की गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची करीब 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं. इस घटना में अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

माली के सैन्य शिविर पर किया हमला, 21 सैनिकों की मौत

एजेंसी। मध्य माली में सेना के एक शिविर पर संदिग्ध जिहादियों के हमले में 21 सैनिक मारे गए हैं.

इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताई पर्रिकर की जिंदादिली की कहानी

नई दिल्ली (आरएनएस)। गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का अंत्येष्टि सोमवार शाम को की जाएगी। कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बाद रविवार को उनका निधन हो गया। पार्रिकर के पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए शाम 5 बजे गोवा खेल प्राधिकरण के मैदान में ले जाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय शोक और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की घोषणा की है। वहीं पार्रिकर का इलाज कर रहे डाक्टर ने पर्रिकर की जिंदा दिली की मिसाल देते हुए कुछ लम्हों को शेयर किया है।

अस्पताल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ. पी जगन्नाथ ने कहा कि 15 फरवरी 2018 का दिन था। मुझे बताया गया कि एक वीवीआईपी को गोवा से लीलावती हॉस्पिटल लाया गया है। उन्हें पेट में दर्द

वह मुस्करा रहे थे...

है और अग्नाशय संबंधी किसी समस्या का शक है। वीवीआईपी होने के चलते अस्पताल ने तैयारी पूरी कर ली थी। मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। वह मनोहर पर्रिकर थे। डॉक्टर ने कहा कि वह बिल्कुल तरोताजा दिख रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि वह बीमार हैं। देर शाम जब उनकी रिपोर्ट आई तो मैं थोड़ा दुखी था। उनके अग्नाशय में कुछ जख्म थे। दुर्भाग्य से अग्नाशय के जख्मों का शुरुआती लक्षण बहुत कम दिखता है।

डॉक्टर जगन्नाथ ने कहा जब पार्रिकर अस्पताल में भर्ती थे, तो पीएम मोदी उन्हें देखने आए। प्रधानमंत्री बेहद परेशान थे कि उनके अहम सहयोगी को यह गंभीर बीमारी हुई है। पर्रिकर ने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी से कहा कि वह सिर्फ गोवा के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में जो भी सबसे अच्छा हो, वह पर्रिकर के लिए किया जाए। इंटरनैशनल हेपाटो पैनक्रिएटो बाइलेरी असोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते न्यू यॉर्क स्थित मेमोरियल स्लोअन केटरिंग के मेरे कुछ साथी डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए तैयार हो गए।

कस्टडी की लड़ाई के प्रभाव दुखद होते हैं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। कई बार कोर्ट पारिवारिक विवाद निपटाने हेतु व्यावहारिक सलाह भी देती हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में रहनेवाले दंपती की बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने दंपती से आपसी समझौते से मामले को निपटाने की सलाह दी और कहा कि वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ाव को निभाने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। कोर्ट ने अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक महिला को बच्चों के साथ वापस अमेरिका लौटने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो यूएस मिशन बच्चों को अपने संरक्षण में ले लेगा।

पैरेंट्स की बच्चों के प्रति होती है बड़ी जिम्मेदारी

जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, पति-पत्नी हर रिश्ते में

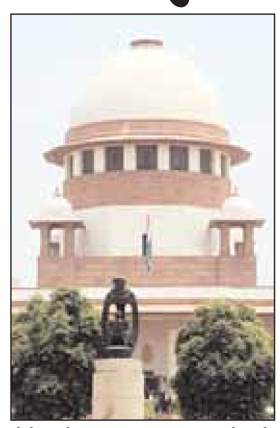

होनेवाले तात्कालिक झगड़ों से बाहर निकल जाते हैं, न कि त्वरित भावनाओं के ज्वार में आकर इसे और बढ़ाते हैं। पैरेंट्स सिर्फ बच्चों के केयरटेकर नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों की सामाजिकता के विकास, भावनात्मकता, समझ-बूझ और शारीरिक देखभाल का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसके लिए पैरेंट्स को आपसी सहयोग के जरिए खुशहाल घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

एनआरआई महिला को बच्चों के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश

बेंच अमेरिका में रहनेवाले एनआरआई कपल के तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी मामले की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने महिला को दोनों बच्चों के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश दिया। दोनों ही अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन तलाक विवाद के बाद महिला बच्चों को लेकर भारत आ गई थीं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, तलाक और कस्टडी का संघर्ष दलदल में फंसने की तरह है। मासूम बच्चे इस संघर्ष से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और इसे देखना दर्दनाक अनुभव है। बच्चे पैरेंट्स की होनेवाली कानूनी और मनोवैज्ञानिक लड़ाई में बुरे तरह फंस जाते हैं। इस केस में अमेरिका में रहनेवाले पति-पत्नी दोनों ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। अपने 7 साल के बेटे और 5 साल की बेटी की कस्टडी का विवाद 2016 से चल रहा है।

आंध्र प्रदेश की 123 और अरुणाचल की 54 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश की 123 और अरुणाचल प्रदेश की 54 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। शेष बचे उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुक्तो विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे।

ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के साथ-साथ चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी कराए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल दोनों ही राज्यों में पहले चरण में 11 अप्रैल को सभी सीटों पर मतदान कराया जाएगा। नतीजे 23 मई को आएंगे।

आंध्र प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव

तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सामने इस चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है। वहीं जगन मोहन रेड्डी अपनी पार्टी वाईआरएस कांग्रेस को इस चुनाव में जीत दिलाकर पिता राजशेखर रेड्डी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

अरुणाचल में जीती थी कांग्रेस पर है बीजेपी सरकार

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार यहां 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे।

दोस्ती कर पहले फिल्म दिखाई, फिर कोल्ड ड्रिंक पिला कर दी हत्या

बदले की आग में झुलस रहा था युवक

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्वी दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की 9वीं की छात्रा को 12 वीं के छात्र ने थोड़ी से कहासुनी को लेकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि ट्यूशन क्लास में दोनों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था। आरोपी छात्र ने हत्या को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसके मन में ट्यूशन क्लास में हुई कहासुनी की बात कई दिनों से चुभ रही थी। पुलिस के मुताबिक, हत्या आरोपी छात्र की पहचान लड़की से ट्यूशन क्लास में हुई थी।

उनकी ट्यूशन में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके कुछ दिन बाद वो एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई। लेकिन यह दोस्ती लड़के ने उस बात का बदला लेने के लिए की थी, जो उसे कहासुनी के दौरान दिल में चुभ गई थी। इसके बाद आरोपी छात्र शनिवार को लड़की को फिल्म दिखाने के बहाने ले गया। फिर शाम को वेलकम मेट्रो स्टेशन के नजदीक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गए। आरोपी ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़की को पिलाया।

फिर लड़की को मार डाला। देर शाम तक लड़की घर नहीं लौटी तो घरवाले पुलिस के पास पहुंचे। मोबाइल कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। पूछताछ में लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि, लड़की के परिवार वालों का कहना है कि फिरौती के लिए लड़की की हत्या की गई।

भीम आर्मी ने कांग्रेस को समर्थन देने से किया इंकार

प्रियंका गांधी की पहली कोशिश नाकाम

सहारनपुर (आरएनएस)। दलितों का हितैषी बनने का दावा करने वाली कांग्रेस को करारा झटका लगा है। ये झटका दिया है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने। रतन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करने की कोई वजह ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया।

हाल ही में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी की मुलाकात हुई जिसके बाद कांग्रेस दलित वोट बैंक की सेंध लगाने की कोशिश में थी। विनय रतन सिंह का बयान दर्शाता है कि प्रियंका की राजनीतिक मुलाकात भी दलितों का वोट कांग्रेस को नहीं दिला पाएगी। चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी की मुलाकात के बारे में विनय ने कहा, वह चंद्रशेखर भाई से मिलना चाहती थीं लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने विशेष अनुरोध किया और कुछ मिनट के लिए मुलाकात हुई। इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में एक रैली के दौरान चंद्रशेखर ने कहा था कि वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे।

अपना केस खुद लड़ेगा 50 लोगों का हत्यारा, वकील को हटाया

न्यूजीलैंड हमला

मॉस्को (आरएनएस)। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की मस्जिदों पर हुई गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी ब्रेंटन टैरंट (28) ने अपने वकील को हटा दिया है। उसने कोर्ट को बताया है कि वह अपने मामले को खुद पेश करेगा। माना जा रहा है कि ब्रेंटन भविष्य में होने वाली कोर्ट ट्रॉयल का इस्तेमाल अपने चरमपंथी विचारों को जाहिर करने के लिए कर सकता है।

दरअसल, टैरंट को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया था। टैरंट के अटॉर्नी रिचर्ड पीटर्स ने क्राइस्ट चर्च

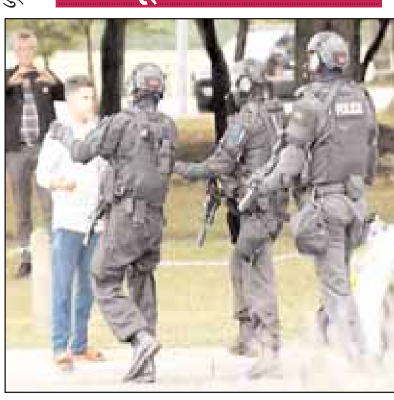

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया कि आरोपी दिमागी रूप से स्थिर है और अपना पक्ष खुद रखना चाहता है। उन्होंने बताया कि टैरंट ने उन्हें शनिवार से इस केस से हट जाने की विनती की है। शनिवार को हत्या के आरोप में पेश हुए टैरंट को पांच अप्रैल तक हिरासत की मांग की गई है।

उन्होंने बताया कि जब वह कोर्ट में पहुंचा तब सब हैरान रह गए। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था बल्कि वह कोर्ट में खड़ा मुस्करा रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे की एक भी शिकन नहीं थी।

जयाप्रदा को टिकट देगी भाजपा

रामपुर में आजम खान को देंगी सीधी टक्कर

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सभी पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने में जुट गई हैं।

भाजपा शनिवार देर रात तक इस बात को लेकर मंथन करती रही कि टिकट किये दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। इस बीच खबर यह आ रही है कि भाजपा जयाप्रदा को चुनावी मैदान में उतारने के मूड में है। कहा जा रहा है कि भाजपा जया प्रदा को रामपुर से उतार सकती है। प्रदेश पैनल में भी जया प्रदा का नाम रामपुर से लिया गया है। हालांकि

रामपुर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और वर्तमान सांसद नेपाल सिंह के बेटे का भी नाम चल रहा है।

उधर खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी रामपुर से आजम खान को उतार सकती है। अगर दोनों पार्टियां जया और आजम खान का नाम फाइनल कर देती हैं तो रामपुर में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा।

देश को मिलेगा पहला लोकपाल

जस्टिस पीसी घोष का नाम तय

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के नाम पर सक्रियता से विचार किये जाने की जानकारी मिली है।

अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। मई 2017 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य हैं।

अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति द्वारा इस पद के लिए उनके नाम पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। समिति में पीएम मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भारत के मुख्य न्यायधीश जस्टिस रंजन गोगोई और प्रख्यात कानूनविद् मुकुल रोहतगी भी शामिल हैं। हालांकि, सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार द्वारा यदि उनकी नियुक्ति की जाती है तो विवाद

उत्पन्न हो सकता है क्योंकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया था।

लोकपाल कानून 2013 में पारित किया गया था जो कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। लोकपाल के लिए बनाई गई समिति में लोकपाल के लिए 10 नामों का चयन किया गया था, जिसमें जस्टिस घोष का भी नाम शामिल था। मई, 2017 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत होने के बाद जस्टिस घोष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ज्वॉइन कर लिया था।

भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकपाल नियुक्ति में देरी के विरोध में आंदोलन का एक और दौर शुरू किया था, जिसके बाद लोकपाल के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उन्होंने अपना आन्दोलन इस वादे के बाद समाप्त किया कि जल्द ही लोकपाल का गठन किया जाएगा।

एनजीटी ने राज्य सरकार से पांच करोड़ भुगतान करने कहा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नदी प्रदूषण

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नदियों के प्रदूषण नियंत्रण में राज्य सरकार असफल रही है इसके चलते राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नदी संरक्षण कार्ययोजना लागू करने के लिए 'निष्पादन गारंटी' के तौर पर पांच करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिलों के प्रभावित लोगों को जलापूर्ति पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। पीठ ने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य की गंभीर असफलता और नदियों में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनजर, हमें निष्पादन गारंटी के रूप में पांच करोड़ रुपये की राशि दिया जाना उचित लगता है। यह राशि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देगी ताकि छह महीने के भीतर कार्य योजना को लागू किया जा सके। वहीं कार्य योजना सौंपने के लिए गठित समिति ने एनजीटी को बताया कि मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण अशोधित सीवेज का नदियों में गिरना है।